IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

Impact Factor: 6.252

Volume 2, Issue 2, December 2022

रीवा जिले के महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता दशा और दिशा

डॉ. अखिलेश कुमार द्विवेदी

एम. ए., एम. फिल, पी. एच. डी. (राजनीति विज्ञान)

शोध सारांशः महिलाओं को अपने किसी भी प्रकार के अधिकारों के लिए अक्सर संघर्ष करते हुए क्यों देखा जाता है ? समाज में समानता का अधिकार जैसे जीवनसाथी चुनने, नौकरी करने या न करने, विवाह करने या अविवाहित रहने, यहाँ तक कि अपने जीवन को अपने इच्छानुसार जीने, सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के हस्तक्षेप के बिना कार्य करने राजनैतिकरूप से सहभागिता निभाने, मतदान करने आदि अधिकारों को क्या महिलाओं ने अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना पाई है? यदि नहीं तो फिर कैसा महिला सबलीकरण? भारतीय समाज में पुरूष सत्ता के मूल्यों के आधार पर महिलाओं का सामाजीकरण कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है कि महिला के अस्तित्व को पुरूष से भिन्न करके देखा ही नहीं जाता है। महिलाओं के जीवन से जुड़ा प्रत्येक निर्णय पुरूष सत्ता ही तय करती चली आ रही हैं इस परम्परा पर पाबंदी नितान्त आवश्यक है और यह तभी संभव हो सकता है जब पूँजीवादी व्यवस्था व पितृसत्ता का पूर्णतया अन्त हो जाय। महिलाओं से अपनी इच्छानुसार वर्ताव कराने के लिए पुरूषों ने हमेशा से भय के मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। जैसे परिवार की मर्यादा के नाम पर कभी उसे शारीरिक और बौद्धिक कमजोर होने का यकीन दिलाना, परिवार व पति की सेवा को उसका धर्म व मुक्ति का मार्ग बताना, घर–परिवार के इच्छा विपरीत किसी भी काम में सहभागिता न बनना लोक –लज्जा आदि का तर्क देकर महिलाओं को सदा ही अपने अधीन बनाएं रखना चाहता है। भारतीय समाज में इसी तरह की अनेकानेक किंवदंतियां एवं पूर्वाग्रह का इतिहास लंबा है। विडंबना यह है कि समाज के आधुनिक व शिक्षित वर्ग भी आज तक इन रूढ़ियों व पुरातन परंपराओं पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पाया या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि इन कुरीतियों पर अंकुश लगाना ही नही चाहता है।

उल्लेखनीय है कि इतना सारा सामाजिक दंश झेलने के बाद महिलाएं स्वयं सास और माँ के रूप में अपने बहू व बेटी को पितृसत्तात्मक समाज के अधीन जीवन यापन करने का उपदेश देती सर्वदा देखी जाती है, उनका कहना है कि लड़कियाँ लड़कों के तुलना में बौद्धिक व मानसिक रूप से कम परिपक्व होने के कारण उन्हें नियन्त्रित व निर्देशित रहना जरूरी होता है। सेसी परिस्थिति में महिला सामाजीकरण व उनका सबलीकरण का कथन आज विरोधाभाषी नजर आता है। यदि महिलाओं का सामाजीकरण पुरूष सत्ता के अन्तर्गत हो रहा है, तो उनके वास्तविक सबलीकरण की बात बेमानी के अलावा कुछ नहीं है, अन्यथा लोकसभा में एक बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक कब का ही पारित हो चुका होता, क्या महिलाओं के सबलीकरण से पुरुषों के लिए समाज के समक्ष विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न हो जाएँगी जिसके भय से महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोंका जा रहा है ? यह एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जिस पर विमर्श करने से भी लोग

कतराते है, महिलाओं के संदर्भ में ऐसे अनेक प्रश्न है जिन पर विमर्श अथवा सार्वजनिक चर्चा करने की जरूरत सदियों से अनुभव की जाती रही है, परन्तु समाज, सरकार, बौद्धिक जगत, शिक्षित जगत आदि सभी अक्सर खामोश नजर आते है अथवा कुछ औपचारिकताओं तक ही सीमित रह जाते है।

अध्ययन से पता चलता है कि रीवा जिले में भी महिलाओं की स्थिति कमोवेश उपरोक्तानुसार ही है यहाँ पर भी महिलाओं की स्वतंत्रता उदारता और खुलेपन को घर–परिवार और समाज विरोधी आज भी समझा जाता है। महिलाओं को स्वतंत्र परिवेश से अलग रखा जाता है और जीवन में संतुष्टि निर्भरता से ही मितली है का विचार महिला के व्यक्तित्व का हिस्सा बना दिया जाता है। घर की चारदीवारी यानि की परिवार पति बच्चे व रसोई पर तो उसे चर्चा करने का हक है परन्तु इस दायरे के बाहर की दुनिया उसके चिंतन का विषय क्षेत्र नही हो सकता हैं।

आज के दौर में ज्ञान ही शक्ति है का तर्क यह संदेश देता है कि महिलाओं को भी ज्ञान के क्षेत्र में इतना गहराई से उतरना होगा कि वह न सिर्फ हर प्रकार के भय का सामना कर सके बल्कि इस सभ्य कहे जाने वाले आधुनिक समाज में एक शिष्ट जीवन व्यतीत कर सकें, समाज में कंधे–से–कंधा मिलाकर समानता के भाव से जीवन के समस्त पहलू जैसे सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का भी निर्वहन कर सकें। ज्ञान की इस शक्ति द्वारा ही महिला न केवल अपनें शोषण से मुक्ति पा सकती है बल्कि शाक्ति संबंधों में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती है।

मुख्य शब्दः समाज, राजनीतिक सहभागिता, सबलीकरण, पिछड़ापन, अग्रणी, भूमिका, प्रतिनिधित्व, समानता, आरक्षण, मतदान, व्यवहार, अधीनता, पितृसत्ता ।

प्रस्तावनाः

राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य संघटक है प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं में यह अत्याधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें नागरिकों से भागीदारी की आशा की जाती है। यद्यपि अधिकतर देशों में राजनीतिक शक्ति केवल कुछ लोगों में ही केंद्रित होती है फिर भी ये सत्ताधारी लोग जनसाधारण को राज्य के मामलों में राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रेरित करते है ताकि राजनीतिक सत्ता को सबल बनाया जा सके और राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व एवं निरन्तरता बनाए रखा जा सकें अगर किसी समाज में अधिकांश जनता को राजनीतिक सहभागिता का अवसर नही दिया जाता या इससे वंचित रखा जाता है तो वहाँ विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है–

- मैथ्यूज तथा प्रोथो के अनुसार '' जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से संबंधित सभी प्रकार का व्यवहार राजनीतिक सहभागिता होती है।''[1]

- मैक ग्लास्की के अनुसार ''राजनैतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं जिनके द्वारा समाज के शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जननीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं।''

संक्षेप में, राजनैतिक सहभागिता व्यक्ति का ऐसा राजनैतिक कृत्य है जिससे राजनैतिक पद धारकों का चयन व उसकी निर्णयकारिता प्रभावित होती हैं।[2]

अतः राजनीतिक सहभागिता के विषय का संबंध उन स्वैच्छिक गतिविधियों से है जिनके द्वारा किसी समाज के सदस्य अपने शासकों के चयन तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में भाग लेते है। ये गतिविधियाँ मत देने, सूचना प्राप्त करने, परिचर्चा करने, सभाओं में भाग लेने, राजनीतिक दलों को चंदा देने, हड़ताल तथा प्रदर्शन आयोजित करने, विधायकों व अन्य अग्रगण्य व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण करने आदि जैसी है।[3]

भारत के मानचित्र पर रीवा जिला की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः कहा जा सकता है कि यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य से प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति प्रभावित होती है। अतः राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन खासकर महिलाओं के राजनैतिक सहभागिता के प्रश्न पर अध्ययन निश्चित तौर पर अपेक्षित हो जाता है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा जिले की महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यः

- रीवा जिले के महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- रीवा जिले की महिलाओं का राजनीतिक सहभागिता का ऐतिहासिक परिदृश्य का अध्ययन करना।
- रीवा जिले में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करना।
- रीवा जिले में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयासों का अध्ययन।
- रीवा जिले में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को अपने संगठनात्मक ढाँचे में शामिल करने का अध्ययन ।

अध्ययन की सीमाएँ– प्रस्तुत शोध रीवा जिले की महिलाओं के सक्रिय राजनीतिक सहभागिता का सौद्धांतिक अध्ययन है अतः यह शोध रीवा जिले की भौगोलिक व राजनैतिक परिधि तक सीमित है।

अध्ययन प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन के द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रमुख रूप से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता संबंधी पुस्तकों पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट एवं जिला निर्वाचन कार्यालय रीवा से निर्वाचन संबंधी प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विषय वस्तु का विश्लेषण किया गया है।

प्राकल्पना –

- शासन–प्रशासन के संचालन हेतु नागरिकों के समान रूप से विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता आवश्यक होती है।
- रीवा जिले में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में सक्रिय राजनीतिक सहभागिा के प्रति निरूत्साह देखने को मिलता है।
- रीवा जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को अपने संगठनात्मक ढाँचे से जोड़ने में उत्साह नही दिखाया जाता है।
- रीवा जिले में महिलाओं के सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में बाधा के रूप में प्रमुख रूप से यहाँ के समाज में व्याप्त रूढ़ियों का नाम आता है।
- स्त्री शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से बढ़ाने में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को गतिशील करने में महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सकती है।

रीवा जिले में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की दशाः

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति को उस समाज में महिलाओं की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है; महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देश–काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में भी अनेक परिवर्तन हुए जिससे महिलाओं की दशा में दिन–प्रति–दिन गिरावट आती चली गई तथा गरीब महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा क्योंकि सैकड़ों वर्षो की परतन्त्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु और भोजन है। महिलाएँ ही संतति की परंपरा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक महिलाएँ उपेक्षित ही रही है उन्हें कम–से–कम सुविधाओं अधिकारों एवं उन्नति के अवसरों में रखा जाता है इसी कारण से महिलाओं की परिस्थिति अत्यंत निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्थाओं में महिलाएँ आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती है। भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिए जाने के बावजूद भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक स्तर की दृष्टि से महिलाएँ अभी भी पुरूषों से काफी पिछड़ी हुई हैं। भारतीय समाज में महिलायें आज भी कमजोर वर्ग में शामिल हैं। महिला परिवार की आधारशिला होती है और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सद्प्रयासों से सम्भव होता है जिस समाज की महिलायें उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती है वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता।[4]

रीवा जिले में महिलाओं की राजनीतिक रूप से कम भागीदारी के मुख्य कारणों में पितृसत्तात्मक समाज तथा इसकी संरचनात्मक खामियों के कारण है। इसी वजह से महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में कम अवसर मिलते है। तथा वे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में काफी पीछे रह जाती है, यहाँ पर अधिकांश महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियाँ जैसे बच्चों की देखभाल घर के सदस्यों के लिए खाना बनाना व अन्य पारिवारिक कारणों से राजनीति में भाग नही ले पाती है। अतः विंध्य क्षेत्र (रीवा) की युवा कवित्री इन्दु श्रीवास्तव की निम्न पंक्तियाँ आंचलिक भाव बोध के साथ समूचे भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं की दशा को उकेरती है। यह पंक्तियाँ इस प्रकार है।

"कानों से सुन, मुँह से मत कह।
औरत है तू , औरत सी रह।।"

इस जिले में निवास करने वाली महिलाओं के अवसरों की कमी उद्योगधंधों का अभाव, आर्थिक तंगी, शिक्षा की कमी एवं सामाजिक पारंपरिक मान मूल्यों की जकड़न, मसलन जातिवाद, बहुदेववाद, टोने –टोटके की आस्था अवयस्क विवाह प्रथा एवं भाषा व लोकजीवन जो उसे इस परिधि से बाहर नहीं निकलने देते है जिसके परिणाम स्वरूप इस भू–भाग से न तो कोई बड़ी राजनेत्री निकलकर आ पाई और न ही कवि कलाकार चिंतक के रूप में ही किसी बड़े हस्ताक्षर का नाम मिलता है। यहाँ पर प्रायः देखा गया है कि कमजोर सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलायें राजनीतिक भागीदारी से दूर रह जाती है परन्तु उच्च जाति की महिलाओं के लिए राजनीति में भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है। निःसंदेह कहा जा सकता हैं कि इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का व्यापक अभाव है।

रीवा जिले में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की दिशा

उन्नीसवीं शताब्दी के उतरार्ध में प्रारंभ हुए सुधारवादी आंदोलनों ने भारतीय समाज की संरचना को गहराई से प्रभावित किया। समाज के विभिन्न वर्गो में व्याप्त जड़ता के खंडित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई इन वर्गो में अपने दायित्व बोध की भावना प्रबल हुई। सामाजिक विकास में इन वर्गो ने अपनी महत्ता और भूमिका को भली भाँति समझा इस नवोदित चेतना के परिणामस्वरूप ये वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े पैमाने पर शामिल हुए दलित पिछड़े वर्गो के साथ–साथ महिलायें भी इस नई चेतना से सुसज्जित हुई, समाज ने महिलाओं के प्रगति पर जो प्रतिबंध लगाए हुए थे वे एक–एक करके समाप्त होने लगें उनमें से कुछ ने शिक्षाण संस्थानों की दहलीज पर दस्तक दी तो कुछ ने सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती दी बहुत –सी महिलायें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने लगी। स्वतंत्रता के बाद संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान किए गए जिनसे इन वर्गो को आगे बढ़ने के विशेष अवसर मिले। महिलाओं को पुरूषों के समान विकास के अवसरों की गारंटी संविधान में दी गई है, संवैधानिक प्रावधानों के कारण बड़े पैमाने पर शासन स्तर पर ऐसे अनेक योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही है जो महिला विकास पर केंद्रित है।[5]

रीवा जिले में अस्सी के दशक तक यहाँ की महिलाओं की दशा अपने पारम्परिक व्यवसाय में दोयम दर्जे की थी । परम्परा एक अदद तक विकास में बाधक हो सकती है परन्तु धीरे–धीरे राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए समाज के अंतिम छोर की महिलाओं तक विभिन्न योजनाओं जैसे बालिका शिक्षा, गाँव की बेटी योजना, जननी प्रसव योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिला सशक्तिकरण नीति, भ्रूण हत्या निरोधक कानून, वयस्क विवाह कानून, महिला आरक्षण नीति, महिला उत्पीड़न निरोधक कानून एवं सम्पत्ति का उत्तराधिकार कानून आदि के माध्यम से किये जा रहे प्रयासों से सार्थक परिणाम आने लगे है और इस क्षेत्र में महिला विकास का चक्र चल पड़ा है।[6]

आज इस क्षेत्र मे महिलायें राजनीतिक रूप से भी जागरूक हो रही है विगत पिछले कई निर्वाचनों में महिला मत प्रतिशत में वृद्धि यह बताता है कि मतदान के प्रति महिलाओं का रूझान बढ़ा है। अतः विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के थोक मतदान को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें अपने संगठनात्मक ढाँचे में भी पदाधिकारी नियुक्त कर रहे है एवं चुनावी राजनीति में भी प्रत्याशी के रूप में भी चुनावी मैदान में उतार रहे है जिसमें महिलाएँ भी बड़ें उत्साह से पूरे मनोयोग से बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही है।

निष्कर्ष एवं सुझावः

उपरोक्त अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में अधिक गिरावट मूलतः मध्ययुगीन काल की देन है इस काल में भारतीय समाज में विभिन्न कुरीतियों एवं बुराइयों के कारण महिलाओं की स्थिति में बहुत गिरावट आई। धीरे–धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाओं के विकास हेतु हमारे आयोजना का केंद्रिय विषय महिला उत्थान निश्चित तौर पर रहा है जो 1970 के दशक में महिला कल्याण की अवधारणा वहीं, 1980 के दशक में महिला विकास पर जोर एवं 1990 के दशक में महिला सशक्तिकरण के प्रयास प्रमुख रूप से स्पष्ट होता है जिसका प्रभाव रीवा जिले में भी निश्चित तौर पर देखा जा सकता है महिला राजनीतिक सहभागिता रीवा जिले में अपनी अब अलग पहचान बनाती नजर आ रही है। चुनाव –दर –चुनाव मतदाता सूची में महिला नामांकन में तो वृद्धि हो ही रही है। व सक्रिय राजनीति में भी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। यद्यपि महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी आवश्यकता है – व्यक्ति, परिवार, समाज के रूपों में समतामूलक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अनुवर्तनी की मानसिकता से ऊपर उठ कर सहकर्मी की मान्यता देने के साथ ही, महिलाओं को भी वैशाखी के सहारे जीने के बजाय स्वावलंबन की राह खोजने की चेष्टा करनी होगी। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत सामूहिकता होती है अतः महिलाओं को भी अपनी आत्मशक्ति के साथ –साथ सामूहिक शक्ति को जागृत करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

[1]. डॉ. धर्मवीर, राजनैतिक समाज शास्त्र राजस्थन हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2019, पृष्ठ सं. 164–165।

[2]. बघेल डॉ. डी. एस. एवं सिंह कर्चुली डॉ. टी.पी., राजनैतिक समाज शास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2013 पृष्ठ सं. 211।

[3]. जौहरी डॉ. जे. सी., राजनीतिक समाज शास्त्र, एस. बी. पी. डी. पब्लिकेशन आगरा, 2019 पृष्ठ सं. 32।

[4]. डॉ. (श्रीमती) सुशीला द्विवेदी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति शोध सारांश स्मारिका, शोध संगोष्ठी, राजनीतिविज्ञान विभाग, शा. ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, 2008 पृष्ठ सं. 28।

[5]. मृदुला सिंह, स्त्रियों के सबलीकरण की दिशा में इक्कीसवीं सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग नई दिल्ली –2001 पृष्ठ सं. 135–136।

[6]. के.के.शर्मा, विंध्यक्षेत्र में महिलाओं की प्रस्थिति (समस्याएँ समाधान) स्मारिका, शोध पत्रों का सारांश, 2008 शा. ठा. रणमत महा विद्यालय रीवा, पृष्ठ सं. 21–22 ।